

जनसत्ता 28 जुलाई, 2014 : संघ लोकसेवा आयोग की नई परीक्षा पद्धति के विरोध में बीते शुक्रवार को दिल्ली में फिर हजारों छात्र सड़कें पर उतर आए। संसद का घेराव करने जा रहे इन छात्रों को पुलिस के दमन का शिकार होना पड़ा। लेकिन विरोध-प्रदर्शन का यह असर जरूर हुआ कि संसद के दोनों सदन में उनके मुद्दे पर चर्चा हुई और सरकार को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। कर्मकिराज्यमंत्री जतिंदर सिंह ने कहा कि सरकार ने शक्तियों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जो कि कहफते के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसी के साथ उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी भाषा के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। यह पहला मौका नहीं है जब सविलि सेवा परीक्षा में कि बदलावों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूटा हो। पछिले महीने भी हजारों की तादाद में वे सड़कें पर उतरे थे और प्रधानमंत्री से मिलने की केशशि में उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी थीं। तब भी कर्मकिराज्यमंत्री ने जल्द उनकी शक्तियों दूर करने का वादा किया था। अब वे समिति की रिपोर्ट आने का इंतजार करने को कह रहे हैं। इस बीच सरकार या समिति ने क्या किया? जबकि यूपी ससी ने अगली परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र जारी करना शुरू कर दिया। इससे विद्यार्थियों का गुस्सा फूटना ही था। सरकार का कहना है कि आयोग अपने कैलेंडर के मुताबिक काम कर रहा है। पर सवाल है कि मंत्री महोदय ने पछिले महीने जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ। यह सही है कि यूपी ससी का संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है और उसकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आयोग अपने बनाये नयियों पर पुनर्विचार नहीं कर सकता, जबकि उनके लेकर खासा विवाद खड़ा हो गया हो।

सविलि सेवा परीक्षा की नई पद्धति के खिलाफ पैली नाराजगी की वजह यह है कि हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को माध्यम चुनने वाले अभ्यर्थियों के प्रति वह भेदभाव से भरी हुई है। भाषाई अन्याय के साथ वर्ग-भेद का भी मामला है, क्योंकि जब से यह परीक्षा पद्धति लागू हुई है, अंगरेजी को छोड़ कर अन्य भाषाओं के अभ्यर्थियों के सफल होने की संख्या तो तेजी से घटी ही है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गद्यांश आधारित प्रश्नों के अंगरेजी से कि गणि अनुवाद ने भी समस्या बसाई है; ये विचित्र ढंग से अनूदित कि गणि प्रश्न ऐसी दुरूह हिंदी में होते हैं जो किसी के पल्ले नहीं पड़ते। इन शक्तियों को यह कह कर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये विद्यार्थी की मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर उनकी सफलता की दर वर्ष 2011 से पहले क्यों संतोषजनक थी, और परीक्षा पद्धति बदलने के साथ ही वह क्यों तेजी से लुप्त की चली गई? नई परीक्षा पद्धति की पैरवी करने वालों की दलील है कि आज के समय में नौकशाही में जाने के इच्छुक लोगों को अंगरेजी, कंप्यूटर, गणित आदि का ज्ञान होना ही चाहिए। पर यही बात भारतीय भाषाओं, अपने समाज और संस्कृति की बाबत ज्ञान को लेकर भी कही जा सकती है। असल सवाल संतुलन बठाने का है। सविलि सेवा परीक्षा के तौर-तरीकों में कई बार बदलाव हुआ है और आगे भी कि जा सकते हैं। पर ये परिवर्तन ऐसे नहीं होने चाहिए कि का खास पृष्ठभूमि से आने वालों के प्रति पक्षपात की मंशा से कि गणि जान पड़े।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>